

प्रियंक,

आर०डॉ०फलीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्श,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2

देहरादून : दिनांक : 02 अगस्त, 2007

विषय: मसूरी, जिला देहरादून स्थित न्याय विभाग के सेशन हाउस की मरम्मत एवं सुधार में
सम्बन्धित कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1229/UHC/Admin.B/Const/2005,
दिनांक 11.4.2007 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मसूरी, जिला देहरादून स्थित न्याय
विभाग के सेशन हाउस की मरम्मत एवं सुधार में सम्बन्धित कार्य हेतु रु० 12,78,000/- के
आगणन के सापेक्ष टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित रु० 12,18,000/- (बारह लाख अठारह हजार रुपये
मात्र) की लागत के आगणन की प्रशामकों एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष
2007-08 में रु० 12,18,000/- (बारह लाख अठारह हजार रुपये मात्र) की धनराशि को व्यय किया
जाने की भी स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- (1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा
स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को, जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा
बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का
अनुमोदन आवश्यक होगा । तदुपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।
- (2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम
प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदुपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया
जाय ।
- (3) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार
सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जाय ।
- (4) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि को भर्त्सित रखते
हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य की
सम्पादित किया जाय ।
- (5) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भूतल भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ
अवश्य कर ले जाय । निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण
टिप्पणों के अनुरूप कार्य किया जाय ।
- (6) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की
जाय । एक मद को राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।
- (7) कार्य कराने समय यह सुनिश्चित कर ले कि अतुरक्षण से सम्बन्धित नियमों एवं नार्मस
से अधिक किसी भी स्थिति में व्यय न की जाय । इसका पूर्ण शायिल
कार्यकारी इकाई का होगा ।

- (8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाये जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय ।
- (9) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टार पर्चेज कलस, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समसंबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेंसी/अधिशाली अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे ।
- (10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2008 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।
3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-2008 की आय व्यय की अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत सेखा-शीर्षक "2014 न्याय प्रशासन 00-आयोजन/तर 105-सिविल और सेशन न्यायालय-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश 00-29-अनुक्षण" के नाम से व्यय किया जायेगा ।
4. यह अपेक्षा वित्त अनुभाग-5 के आशमकीय संख्या-734/XXVII(5)/2007, दिनांक 26.7.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहे है ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवान)

सचिव ।

संख्या-16-दी(8)/XXXVI(1)/2007-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निर्मालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं दफ्तरी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
2. जिला न्यायाधीश, देहरादून ।
3. वरिष्ठ कांयाधिकारी, नैनीताल/देहरादून ।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
5. अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
6. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
7. एन०आई०सी०/सम्बन्धित तस्वीर अधिकारी/गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(आशाकि कुमार वर्मा)

अपर सचिव ।